प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
05.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

'' मुख्य समाचार''

- प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी– कांग्रेस की ओर से अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन।
- राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नहीं उतारा उम्मीदवार– कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा का चयन तय।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर डिजिटल उपकरणों का किया शुभारंभ–दो चरणों में होगी जनगणना।
- राज्य सरकार ने हटाया डिजास्टर एक्ट– पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का रास्ता हुआ साफ।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप– कांग्रेस सरकार ने आपदा एक्ट का किया दुरूपयोग।

राज्यसभा नामांकन

कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने आज प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने विधानसभा सचिव के समक्ष नामांकन पत्र भरा और इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। प्रदेश से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और इस सीट को भरने के लिए ये चुनाव करवाया जा रहा है। नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और 9 मार्च को नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि है, जबकि मतदान की तारीख 16 मार्च को निर्धारित है। विपक्षी दल भाजपा ने इस बार राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा का चयन तय माना जा रहा है।

सीएम–अनुराग

इस बीच पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अनुराग शर्मा को राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अनुराग शर्मा कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें टिकट मिलने से सभी कार्यकर्ता खुश हैं।

भाजपा द्वारा उम्मीदवार न उतारने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 40 निष्ठावान विधायक हैं। ऐसे में यदि भाजपा अपना उम्मीदवार उतारती तो उसकी हार तय थी।

अनुराग शर्मा ने कहा कि वे हर मंच पर प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे राज्यसभा में आर.डी.जी. और मनरेगा जैसे मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाएंगे।

गृहमंत्री जनगणना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में चार डिजिटल उपकरणों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2027 की जनगणना के लिए महिलाओं और पुरुषों के प्रतीक शुभंकर– प्रगति और विकास का औपचारिक अनावरण किया। गृह मंत्रालय ने कहा कि उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र ने देश भर में गणना कार्यों को सुगम बनाने के लिए यह उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 16 जून को जनगणना कराने की घोषणा की थी। मंत्रालय ने कहा कि जनगणना–2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी और स्व–गणना का विकल्प भी रहेगा। इसके अंतर्गत घर–घर जाकर सुरक्षित मोबाइल

एप्लिकेशन का उपयोग करके डेटा एकत्र किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए देशभर में 30 लाख से अधिक गणनाकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य जनगणना अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।

डिजास्टर एक्ट

प्रदेश में डिजास्टर एक्ट के हटने के साथ ही पंचायती राज चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने डिजास्टर एक्ट को हटाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पिछले वर्ष 8 अक्तूबर को डिजास्टर एक्ट लागू किया था, जिसके चलते पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को भी टाल दिया गया था। राज्य सरकार ने प्रदेश के अधिकांश भागों में कनैक्टिविटी बहाल होने के बाद डिजास्टर एक्ट को हटाने का निर्णय लिया है।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 6 महीने बाद राज्य सरकार द्वारा डिजास्टर एक्ट हटाए जाने के निर्णय पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मंडी में अपने तीन साल के कार्यकाल पर आयोजित कार्यक्रम में 10 करोड़ रूपए खर्च किए और राहत कार्यों को अनदेखा किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि 8 महीने बाद भी राज्य के अनेक हिस्सों में सड़कों पर मलबा पड़ा है और सैंकड़ों रूट बंद पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों को टालने के लिए ही आपदा एक्ट लागू किया क्योंकि सरकार को अपनी नाकामियों को लेकर जनता के बीच जाने में डर लग रहा है।

चंबा डीसी

चंबा जिले में पंचायती राज चुनावों को लेकर जिले के 18 जिला परिषद वार्डों की परिसीमन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसमें कई पंचायतों के लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी, जिनपर फैसला लेकर अंतिम आदेश जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले के 18 जिला परिषद वार्डों की जनसंख्या चार लाख 79 हज़ार 2 सौ 50 है। उन्होंने बताया कि पंचायत समितियों व पंचायतों का परिसीमन पहले ही कर दिया गया है और 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा।

हर्ष महाजन

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि केंद्र सरकार के नीतिगत सुधारों से भारत का व्यवसायिक माहौल बदल गया है और पंजीकृत कंपनियों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में लगभग 27 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों ने देश में उद्यमिता व निवेश को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की व्यवसाय अनुकूल नीतियों से हिमाचल के युवाओं को भी नए अवसर मिल रहे हैं।

ट्रैकिंग

कांगड़ा जिला प्रशासन ने जिले के ट्रैकिंग स्थलों पर दिन के समय ट्रैकिंग करने की अनुमती दे दी है। पिछले वर्ष दिसंबर के महीने से भारी बर्फबारी को देखते हुए ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई थी। कांगड़ा की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेक्टा ने बताया कि जिले के सभी स्थानों पर अब मौसम साफ हो गया है और बर्फ पिघल चुकी है, ऐसे में प्रशासन ने ट्रैकिंग गतिविधियां फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है लेकिन सुरक्षा के दृष्टिगत रात के समय ट्रैकिंग पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

'' मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी– कांग्रेस की ओर से अनुराग शर्मा ने भरा नामांकन।
- राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नहीं उतारा उम्मीदवार– कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग शर्मा का चयन तय।

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर डिजिटल उपकरणों का किया शुभारंभ–दो चरणों में होगी जनगणना।
- राज्य सरकार ने हटाया डिजास्टर एक्ट– पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का रास्ता हुआ साफ।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप– कांग्रेस सरकार ने आपदा एक्ट का किया दुरूपयोग।